www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 283 | जौनपुर गुरुवार, 04 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रुपये

मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आगजनी की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग में हुई जानमाल की हानि बेहद दुखद है। उन्होंने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीएमएनआरएफ से सहायता राशि का ऐलान पीएम नरेन्द्र मोदी ने इस घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग में हुई जानमाल की हानि बेहद दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।

घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घटना हृदय विदारक है। उन्होंने एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में एक दुर्भाग्यपूर्ण भीषण अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौज रानी स्थित एक रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह है कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर है और 37 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली फायर सर्विस टीम को मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके तुरंत बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के बेसमेंट से ये आग लगनी शुरू हुई। रेस्टोरेंट के बेसमेंट से गंभीर हालत में लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस आग की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है और 37 लोग घायल हैं। घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

संक्षिप्त खबरें

चुनाव में चाय बगान के मजदूरों से किए गए वादे पूरे होंगे : सीएम सरमा

नई दिल्ली, (एजेंसी) ।असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात की। इस मुलकात के दौरान कृषि से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करता हूं कि उनका सहयोग चुनाव के दौरान मिला। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादा चाय बागान के मजदूरों से किया था, वह पूरा किया जाएगा। चाय बागान के श्रमिकों को पीएम आवास योजना के तहत मकान देने का काम किया जाएगा ।सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास दशकों का समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनसे मिलना हमेशा एक ज्ञानवर्धक अनुभव होता है। भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर हमने इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की। किसानों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के तरीके और श्डबल इंजन सरकारश की सभी किसान–हितैषी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना, ताकि उनका लाभ असम के हर किसान तक पहुंच सके।

भाजपा से जुड़े ट्रस्टी वाले स्कूल का नाम उजागर करने पर मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें उन पर यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ यह मामला उस स्कूल का नाम बताने के लिए दर्ज किया गया था, जहां यह घटना हुई थी, क्योंकि उस संस्थान के ट्रस्टियों के भारतीय जनता पार्टी से संबंधा थे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आप नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईएएनएस से घ्बात करते हुए भारद्वाज ने कहा कि मैंने न तो पीड़िता का नाम बताया है और न ही उसके माता–पिता का नाम बताया। मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। स्कूल का नाम बताने की वजह से मेरे खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ तीन केस दर्ज किए गए हैं ।सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि हम तीन साल की बच्ची के साथ हुए रेप का मुद्दा उठा रहे हैं। यह वही केस है जिसमें डीसीपी बच्ची के माता–पिता को बुलाकर परेशान करते हैं। यह वही केस है जिसमें एसएचओ सुबह से शाम तक बच्ची के माता–पिता को परेशान करते हैं।

आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर ही पूरा होगा विकसित भारत का लक्ष्य : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब आदिवासी समुदाय विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जुड़ जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मु एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा, "आदिवासी समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है, लेकिन योजनाओं की जानकारी और लाभ उन्हें समय पर नहीं मिल पाते। आदिवासी परिवार आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं, इसलिए योजनाओं को बार–बार उनके दरवाजे तक ले जाना आवश्यक है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि आईटीडीए और आईटीडीपी के अधिकारी जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को गांव और घर–घर तक पहुंचाएं। इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आदिवासी युवाओं को आधुनिक शिक्षा, तकनीक और कौशल विकास से जोड़ना जरूरी है, ताकि वे बदलते समय के साथ कदम मिला सकें। उन्होंने अधिकारियों से आदिवासी समाज की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने की अपील की। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुर्गादास उइके और मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है।

असम के मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 'मिशन सेनेहजोरी' लॉन्च, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ मिलकर मंगलवार को 'मिशन सेनेहजोरी' का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य असम के पारंपरिक मुगा रेशम क्षेत्र को विश्वस्तरीय, उच्च मूल्य वाले और निर्यातोन्मुख लक्जरी वस्त्र इकोसिस्टम में बदलना है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर के विजन को मिशन सेनेहजोरी के माध्यम से साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम का मुगा रेशम केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का प्रतीक है। इस मिशन का उद्देश्य असम के सुनहरे रेशम को वैश्विक लक्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, असम सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड और वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से संचालित इस मिशन के तहत मेजबान पौधों की खेती, रेशमकीट बीज उत्पादन, रीलिंग, बुनाई, ब्रांडिंग, निर्यात संवर्धन, डिजिटल ट्रेसबिलिटी और पर्यटन सहित पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा। मुगा रेशम को दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम माना जाता है और यह भारत का पहला जीआई–टैग प्राप्त रेशम है। असम में लगभग 2.6 लाख रेशम पालक और बुनकर परिवार इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि वैश्विक पहचान के बावजूद इस क्षेत्र को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया है। मिशन सेनेहजोरी इसी अंतर को दूर करने की दिशा में काम करेगा। यह मिशन जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, माजुली और सुआलकुची जैसे प्रमुख मुगा रेशम उत्पादक जिलों में क्लस्टर आधारित मॉडल पर लागू किया जाएगा। इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने, साझा सुविधा केंद्र स्थापित करने, जीआई प्रमाणीकरण लागू करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की योजना है। सिंधिया ने बताया कि तीन वर्षों की अवधि में इस मिशन के तहत लगभग 396 से 411 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी मुगा रेशम इकोसिस्टम विकसित करना, उत्पादकों की आय बढ़ाना और असम को रेशम आधारित सांस्कृतिक एवं अनुभवात्मक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना है।

2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण होगा माफ, 56 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

मुंबई , (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना' को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों का दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से लगभग 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और वे कर्ज के बोझ से काफी हद तक मुक्त हो सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 36,585 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह रकम राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए किए गए सबसे बड़े वित्तीय आवंटनों में से एक मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और किसानों की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए यह फैसला आवश्यक था। किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ? सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के अनुसार, कर्जमाफी का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका कृषि ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना को व्यापक और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र किसान इसका लाभ उठा सकें। अधिकारियों के अनुसार, पात्रता संबंधी विस्तृत नियम और प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। इसके बाद किसानों को आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी ।सरकार ने केवल डिफॉल्टर किसानों को राहत देने तक खुद को सीमित नहीं रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि जो किसान समय पर अपने ऋण की अदायगी करते रहे हैं और जिन्होंने किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया है, उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और ईमानदारी से ऋण चुकाने वाले किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से नियमित भुगतान करने वाले किसान ऐसी किसी प्रोत्साहन योजना की मांग कर रहे थे।

मध्य्य प्रदेश के भोजशाला में बनेगा भव्य सरस्वती लोक : सीएम मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि धार स्थित भोजशाला परिसर में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी, यहां राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मंत्रि परिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राजा भोजपाल द्वारा स्थापित यह भोजशाला सदियों तक ज्ञान–विज्ञान–अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केन्द्र रहा है। उन्ध्होंने कहा कि यहां दूर–दूर से विद्यार्थी और विद्वान ज्ञान अर्जित करने और शास्त्रों पर विमर्श करने आते थे। राज्य सरकार भोजशाला के उसी गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास करेगी। राजा भोज की कर्मस्थली धार में राजा भोज शोधा संस्थान की भी स्थापना की जाएगी ।उन्होंने कहा कि भोजशाला के लिए हुए आंदोलन में शहादत देने वाले तीन शहीदों बनसिंह, अंतरसिंह एवं लक्ष्मण सिंह के निकटतम परिजन को राज्य सरकार की ओर से 5–5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा के सफल 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। देशवासियों की आशा के प्रतीक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में भारत ने विकास के साथ आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। राष्ट्र प्रथम की भावना से जीवायएएन मंत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान तक, सीमाओं की सुरक्षा से नक्सल व आतंक मुक्त भारत के निर्णायक परिणाम तक, भारत ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री, उनकी सुरक्षा और सुविधा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीएम धामी

देहरादून, (एजेंसी)। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने हेतु एसओपी तैयार करने एवं रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि तीर्थयात्रा के पहले चरण के दौरान, रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने चार धाम मंदिरों के दर्शन किए। पिछले वर्षों की तुलना में तीर्थयात्रियों की संख्या काफी अधिक रही है। तीर्थयात्रियों की संख्या में हुई इस वृद्धि के कारण, प्रशासन, मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों को कुछ स्थानों पर व्यवस्थाओं के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब मानसून का मौसम नजदीक आ रहा है और तीर्थयात्रा अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और कुशल तरीके से काम करती रहें। दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। हमने सड़कों की स्थिति, पेयजल सुविधाओं, आवास, दर्शन की व्यवस्था, हेलीकॉप्टर सेवाओं और परिवहन सुविधाओं की भी समीक्षा की है ।उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अधिक संख्या होने के कारण कहीं–कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसका संज्ञान लिया गया है। रास्तों, पानी, आवास, दर्शन व्यवस्था, हेली सेवाओं, परिवहन और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई है।

राहुल गांधी ने कहा– सीबीएसई चेयरमैन व सचिव को हटाना जवाबदेही नहीं, शिक्षा मंत्री को बचाने का कवर अप है

नई दिल्ली , (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन में ऑन–स्क्रीन मार्किंग को लेकर उपजा विवाद अब देश का सबसे बड़ा सियासी और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े निर्देश पर सरकार ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया ।इस प्रशासनिक फेरबदल के तुरंत बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे श्कवर–अपश (मामले को दबाने की कवायद) करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे अधिकारियों पर गाज गिराकर असल दोषी, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का सरकार पर हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर हिंदी में पोस्ट कर सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस कार्रवाई को महज एक दिखावा बताते हुए लिखा कि ष्सीबीएसई चेयरमैन – हटाए गए। सीबीएसई सचिव – हटाए गए। एक सदस्यीय जांच समिति गठित। और असली दोषी धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटाया गया। मंत्री को बचाया गया। यह जवाबदेही नहीं है। यह कवर–अप है ।ष्राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 18.5 लाख छात्रों के भविष्य की जरा भी परवाह होती, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले ही पद से हटा दिया गया होता। उन्होंने साफ किया कि विपक्ष की मांग आज भी वही हैकृ षशिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। मूल्यांकन में भारी अनियमितताओं की बात सामने आई। इस गड़बड़ी ने लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया था। पीएमओ की सक्रियतारू सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मूल्यांकन विवाद और टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी पर सोमवार को ही एक उच्च स्तरीय रिपोर्ट तलब की थी।

संपादकीय

आरक्षण का मुद्दा गरमाया

चुनाव प्रचार में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रारंभिक तौर पर आरक्षण को सबसे निचले वर्गों की जातियों को आर्थिक तथा राजनीतिक संबल प्रदान करने के लिए वैधानिक तौर पर आरक्षण प्रदान किया गया था। बाद में आरक्षण का विस्तार होता गया और इसमें नये–नये जाति समूह शामिल होते चले गए ।आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाट और मराठा जैसे शक्तिशाली समूहों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। दरअसल, जो आरक्षण निचली पायदान पर खड़े जाति समूहों के उत्थान के लिए था, वह सभी जाति समूहों के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का हथियार बन गया। कहने की जरूरत नहीं है कि आज आरक्षण भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में असंतोष और चिंता का कारक बना हुआ है। हिन्दू समाज के अनारक्षित जाति समूह मानते हैं कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसी सूरत में एक ऐसे आर्थिक ढांचे पर बल दिए जाने की जरूरत थी जिसमें बिना आरक्षण की सीढ़ी के सभी निचले वर्ग के लोगों को उत्थान के अवसर प्राप्त हों और जातीय आग्रह सामाजिक विग्रह के कारण न बनें लेकिन अब आरक्षण की नीति एक चिंताजनक मोड़ पर ले आई है। एक ओर जहां कांग्रेस के नेता विशेषकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरक्षण को मुस्लिम तुष्टिकरण का नया औजार बना लिया है। वह बार–बार कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं जहां कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके पिछड़े वर्ग के कोटे से ही 4 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया जिसे बाद में भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां भाजपा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। मोदी अपनी हर सभा में खुलकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर मुसलमानों को दे देगी। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने चोर दरवाजे से कर्नाटक में आरक्षण देकर जो कदम उठाया है, उसके दुष्परिणाम समझ नहीं पा रही। बेशक, भाजपा को विरोध का बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है।

अमेरिका के सामने भारत इतना दब्बू पहले कभी नहीं रहा

अनिल

आम तौर पर किसी देश का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आता है या भारत के विदेश मंत्री किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो उनकी बात अपने समकक्ष से होती है। इस लिहाज से रुबियो की बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर से होनी चाहिए थी। विदेश मंत्रियों की दोपक्षीय वार्ता में सभी मुद्दों पर बातचीत की जाती है। जो कूटनीति होनी है या जोड़–तोड़ होनी है। यह तय करना निर्वाचित केंद्र सरकार का अधिकार है कि भारत अपनी विदेश नीति में किस दुनिया के किन देशों से अपने रिश्तों को प्राथमिकता दे। फिर भी भारत में विदेश नीति को लेकर हमेशा आम सहमति रही है और सरकारें बदलने पर बाकी नीतियां भले ही बदलती रही हों लेकिन वैदेशिक नीति के मामले में निरंतरता रही है। दुर्भाग्य से यह सिलसिला 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद टूट गया। भारत ने न सिर्फ अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ दिया बल्कि उसने अपने पारंपरिक मित्र देशों से भी बहुत हद तक दूरी बनाकर खुद को पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर बना लिया। यह सही है कि सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत की अमेरिका से निकटता बढ़ गई, जिसका वामपंथी दलों के अलावा देश के किसी भी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। हाल के दिनों में तो यह नीतिगत झुकाव इस हद तक बढ़ गया है कि भारत सरकार की ओर से सामरिक और व्यापारिक मामलों में अमेरिका ही फैसले लेता दिखने लगा है ।यह अफसोसनाक है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त युद्धविराम से लेकर आज तक अनेक महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान अमेरिकी प्रशासन ने भारत सरकार के कुछ कहने से पहले कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तो 50 से ज्यादा मौकों पर इस बात को दोहराया कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को भारत से व्यापार बंद करने की धमकी देकर युद्धविराम के लिए राजी किया। ट्रम्प के इस कथन का भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जरूर दबे स्वरों में खंडन किया और कहा कि श्भारत ने युद्धविराम का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया था, किसी के दबाव में नहीं ।श मगर मोदी ने आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान का प्रतिवाद नहीं किया है। इस बीच ट्रम्प ने मोदी को अपमानित करने जैसे कुछ बयान भी दिए। मसलन, उन्होंने कहा कि, श्वे चाहें तो मोदी का कॅरियर तबाह कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे ।श उनके इस आपत्तिजनक बयान पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे ।यही नहीं, इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच दोपक्षीय व्यापारिक समझौते पर बनी सहमति और उस समझौते की शर्तों का एकतरफा ऐलान भी अमेरिका की ओर से ही कर दिया गया। हालांकि उस समझौते की कई शर्तें विवादास्पद और भारतीय हितों के खिलाफ हैं। फिर भी भारत सरकार आज तक देश को उसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत को रूस और ईरान से तेल खरीदने के लिए मना कर दिया है लेकिन उनके इस बयान का जवाब भी भारत सरकार की ओर से चुप्पी साधकर ही दिया गया। इसके बाद इस सिलसिले में नई कड़ी हाल ही में भारत यात्रा पर आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोड़ी, जब उन्होंने वॉशिंगटन में ही यह ऐलान कर दिया कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और जल्द ही वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोडिगेज नई दिल्ली जाएंगी ।पिछले महीने की 23 तारीख को चार दिनों के लिए भारत आने के बाद मार्को रुबियो ने तो यह घोषणा भी कर डाली कि भारत पांच साल में अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर की खरीदारी करेगा। पहले बताया गया था कि यह खरीदारी अमेरिका से होने वाले दोपक्षीय व्यापार समझौते का हिस्सा होगी। तब ट्रम्प प्रशासन के

टैरिफ वॉर के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। जब फैसला आया तो उसने व्यापार समझौते की पूरी पृष्ठभूमि बदल डाली। बहरहाल, समझौता अभी कहीं अटका हुआ है, जबकि खरीदारी की शर्त पर भारत के सहमत होने की घोषणा रुबियो ने कर डाली है। इस पर भारत सरकार की ओर से विरोध न जताया जाना उनकी बात की पुष्टि के रूप में ही देखा जा सकता है। ऐसे और भी उदाहरण भी हैं, जिनसे अमेरिका दोपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अपने ढंग से पुनर्परिभाषित करता दिख रहा है ।जाहिर है कि वह अपने मित्र अथवा सहयोगी देशों को अपने मातहत दिखाकर अपनी नव–औपनिवेशिक नीति को आगे बढ़ाता मालूम पड़ रहा है। सवाल है कि क्या मोदी सरकार इसमें सहभागी बनने को तैयार है? यह सवाल देश के बड़े जनमत को बेचौन कर रहा है। अमेरिका के सामने भारत की यह स्थिति तब है जब अमेरिका अपना महाशक्ति होने का रुतबा गंवा रहा है। उसकी यह स्थिति ईरान से जारी उसके युद्ध के दौरान साफ दिख रही है। उसने इजरायल के साथ मिलकर विश्व बिरादरी में वर्षों से लगभग अलग–थलग पड़े जिस ईरान को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान चलाया था, उसी ईरान से अब वह समझौते के लिए लालायित नजर आ रहा है। अमेरिका और ट्रम्प की दयनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह युद्धविराम के लिए ईरान को मनाने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। रूस, चीन, इजरायल के अलावा ईरान, तुर्किये, कतर, पाकिस्तान आदि कई इस्लामी देश ट्रम्प के अमेरिका की हैसियत में आ रही गिरावट को समझ रहे हैं। सभी की निगाह में वह थोथा चना बन गया है ।इसके विपरीत 140 की आबादी वाले भारत की सरकार अभी भी अमेरिका को अपना तारणहार मान रही है। इसकी ताजा झलक मार्को रुबियो की हाल की भारत यात्रा के दौरान भी दिखी। रुबियो 23 मई को जब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरे तो वहां की तस्वीरें देखकर भाजपा और सरकार के इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बढ़–चढ़कर प्रचारित किया कि भारत ने अमेरिका को उसकी औकात बता दी। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री की आगवानी करने अमेरिकी राजदूत और भारत सरकार के दो जूनियर अधिकारी पहुंचे थे। सवाल है कि क्या किसी देश का विदेश मंत्री आता है तो विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री उसकी आगवानी करने जाते हैं। कहने का आशय यह है कि प्रोटोकॉल के तहत ही रुबियो को हवाईअड्डे पर रिसीव किया गया था लेकिन सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुके मीडिया ने भी इसे बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया। उसके बाद जो हुआ वह अभूतपूर्व रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री हवाईअड्डे से निकले और दनदनाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे।

विश्व साइकिल दिवस जीवन के लिए जरूरी साइकिल का साथ

कुमार सिद्धार्थ

साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक समय सामाजिक समानता और सादगी का प्रतीक भी रही है। एक दौर में शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान और छोटे अधिकारी सभी साइकिल से यात्रा करते थे। इसमें वर्ग भेद कम दिखाई देता था। यही कारण है कि कई विचारकों ने साइकिल को लोकतांत्रिक वाहन कहा। र वर्ष 3 जून को श्विश्व साइकिल दिवसश मनाया जाता है। श्संयुक्त राष्ट्र संघश ने इस दिवस को इसलिए मान्यता दी ताकि दुनिया को यह याद दिलाया जा सके कि साइकिल केवल दोपहियों वाला साधारण वाहन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और टिकाऊ विकास का प्रभावी साधन है। आज जब दुनिया पेट्रोल–डीजल की बढ़ती कीमतों, ऊर्जा संकट, प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, तब साइकिल फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है ।एक समय था, जब साइकिल भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में आम आदमी के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। आधुनिकता की दौड़ में मोटर वाहनों की चमक–दमक के बीच साइकिल धीरे–धीरे सड़कों से हाशिये पर चली गई। अब दुनिया फिर समझ रही है कि विकास का अर्थ केवल तेज रफ्तार वाहन नहीं, बल्कि ऐसे साधन भी हैं, जो टिकाऊ हों और समाज के लिए लाभकारी हों। आज जब पर्यावरण संरक्षण और श्ग्रीन मोबिलिटीश की बात होती है, तो इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी तकनीक, चार्जिंग स्टेशन और नई परिवहन योजनाओं की खूब चर्चा होती है। सरकारें इलेक्ट्रिक कारों और दो पहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना रही हैं। शहरों में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि इन चर्चाओं के बीच पर्यावरण–अनुकूल साधन, पारंपरिक श्साइकिलश अक्सर गायब हो जाती है ।साइकिल ऐसा वाहन है, जिसे न पेट्रोल चाहिए, न डीजल, न बैटरी और न ही कोई चार्जिंग–स्टेशन। यह पूरी तरह मानव ऊर्जा पर आधारित है। इसके बावजूद शहरी परिवहन योजनाओं में इसे वह प्राथमिकता नहीं मिलती, जिसकी यह हकदार है। कई शहरों में साइकिल लेन की योजनाएं बनीं, लेकिन अनेक जगहों पर वे अतिक्रमण, खराब डिजाइन और उपेक्षा के कारण सफल नहीं हो सकीं। साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक समय सामाजिक समानता और सादगी का प्रतीक भी रही है। एक दौर में शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान और छोटे अधिकारी सभी साइकिल से यात्रा करते थे। इसमें वर्ग भेद कम दिखाई देता था। यही कारण है कि कई विचारकों ने साइकिल को लोकतांत्रिक वाहन कहा ।वर्ष 1960 के बाद जैसे–जैसे मोटर वाहनों की संख्या बढ़ी, साइकिल पीछे छूटने लगी। कारें और बड़े वाहन आधुनिकता और उपभोक्तावाद के प्रतीक बन गए। धीरे–धीरे साइकिल को पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि सड़कों पर कारों का कब्जा बढ़ता गया और साइकिल हाशिये पर चली गई। आज फिर परिस्थितियां बदल रही हैं। दुनिया समझ रही है कि महंगे ईंधन, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु संकट के दौर में साइकिल पिछड़ेपन का नहीं, बल्कि समझदारी और टिकाऊ जीवन शैली का प्रतीक है ।भारत आज भी दुनिया के बड़े साइकिल उपयोग करने वाले देशों में शामिल है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार देश में दस से 12 करोड़ से अधिक परिवारों के पास साइकिल उपलब्ध है। ग्रामीण भारत में इसका उपयोग और भी अधिक है। साइकिल उद्योग के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल एक करोड़ से अधिक नई साइकिलों की बिक्री होती है। पंजाब का लुधियाना देश के साइकिल निर्माण का बड़ा केंद्र माना जाता है। भारत दुनिया के बड़े साइकिल उत्पादक देशों में भी शामिल है। दुनियाभर में साइकिल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व में एक अरब से अधिक साइकिलें उपयोग में हैं। यूरोप, चीन, जापान और एशिया के कई देशों में साइकिल रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। कई देशों में लाखों लोग प्रतिदिन साइकिल से अपने कार्यस्थल पहुंचते हैं। भारत में भी साइकिल प्रेमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब साइकिल केवल ग्रामीण या गरीब का वाहन नहीं रही, बल्कि शहरों में भी आर्थिक रूप से सम्पन्न युवा, पेशेवर, फिटनेस प्रेमी और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग इसे अपना रहे हैं। आज दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय तनाव, युद्ध और आपूर्ति बाधाओं का असर सीधे पेट्रोल–डीजल की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ता है। भारत जैसे देशों में, जहां बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए जाते हैं, इसका असर आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई देता है। इनकी कीमतें बढ़ने से न केवल यात्रा महंगी होती है, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है। ऐसे में साइकिल एक विकल्प है, जो पूरी तरह ईंधन मुक्त है। छोटी दूरी के लिए अगर लोग साइकिल अपनाएं, तो ईंधन की खपत कम होगी, घरेलू खर्च घटेगा। यही कारण है कि ऊर्जा संकट के दौर में श्साइकिल फिर भविष्य के परिवहनश के रूप में देखी जा रही है। देश–दुनिया में कई नेता, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता साइकिल से आने–जाने या सार्वजनिक साइकिल अभियानों में भाग लेने का संदेश देते रहे हैं। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक संकेत है कि सुविधा और जिम्मेदारी के बीच संतुलन संभव है। आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और धरती का तापमान बढ़ता है। साइकिल इस समस्या का सबसे सरल समाधान है। यह न धुआं छोड़ती है, न शोर करती है और न ही सड़क पर अधिक जगह घेरती है। शहरों में अगर छोटी दूरी के लिए साइकिल उपयोग को बढ़ावा मिले, तो प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों कम हो सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई शहरों में अलग श्साइकिल लेन,श सार्वजनिक साइकिल सेवा और सुरक्षित ट्रैक बनाए जा रहे हैं। साइकिल चलाना केवल सफर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी साथी है। यह हृदय को मजबूत बनाती है, वजन नियंत्रित रखती है, मांसपेशियों को सक्रिय करती है और मानसिक तनाव कम करती है। पर्यावरण–अनुकूल परिवहन की चर्चा में अगर साइकिल को फिर केंद्र में लाया जाए, सुरक्षित श्साइकिल लेन्च बनाई जाएं और लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो यह न केवल आम आदमी के लिए राहत होगी, बल्कि देश और दुनिया के लिए भी बड़ा समाधान साबित हो सकती है। सच तो यह है कि साइकिल केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत और भविष्य की दिशा बनकर फिर हमारे सामने खड़ी है। दो पहियों पर चलने वाली यह साधारण सवारी हमें एक स्वस्थ, सस्ता, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सकती है।

इंतजामों को अधिक सक्रिय करने की जरूरत

अनिरुद्ध गौड़

हमारे देश के वनों में गर्मिंयों के दिनों में आग लगना एक लगातार सिलसिला है। अप्रैल का महीना शुरू हुआ कि आग से जंगल धधकने लगते हैं। जंगल की आग पर्यावरण की दृष्टि से तो खतरनाक है ही जनजीवन और बायोडायर्वसटी की दृष्टि से भी हानिकारक है। ऐसे समय में जब जंगलों में आग लगती है तो देखा गया है कि उसकी तैयारी में सरकार विफल रही है। देश के वनों में अप्रैल माह में आग की घटनाओं को देखें तो देश में हाल फिलहाल 361 जगह वनों में आग लगी हैं। इन घटनाओं की निगरानी को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर लांच बीटा संस्करण एसएनपीपी – वीआईआईआरएस का 10 अप्रैल, 2024 का भारत के वनों में लगी भीषण आग का मौजूद आंकड़ा बताता है कि सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में 122, तेलंगाना में 55, छत्तीसगढ़ में 47, उत्तराखंड में 32, बिहार में 23, ओडिसा में 22, उत्तर प्रदेश में 17 सहित 21 राज्यों में 361 जगह आग लगी थी जो 13 अप्रैल को घट कर काबू होने के बाद 33 रह गई। 1अप्रैल को देश के वनों में 132 बड़ी आग लगी थी जो 10 अप्रैल को 361 जगह तक पहुंच गई है। अप्रैल माह में पिछले 7 दिनों का आंकड़ा देखें तो एक्टिव आग की घटनाओं में टॉप फाइव राज्यों में छत्तीसगढ़ में 166, आंध्र प्रदेश में 248, मध्य प्रदेश में 207, ओडिसा में 146 और असम में 139 जगहों पर बड़ी आग लगी। वहीं 1 नवम्बर, 2023 से 2024 में बड़ी आग की घटनाओं में टॉप फाइव राज्यों में आंध्र प्रदेश में 860, मध्य प्रदेश में 719, तेलंगाना 688, महाराष्ट्र में 547 और छत्तीसगढ़ में 527 बार आग लगी, जबकि वर्ष 2022–2023 में तो पूरे देश के वनों में 12562 आग की घटनाएं हुई। जंगल की आग से वनों का क्षरण तो होता ही है बहुमूल्य वन संपदा और कार्बन भी नष्ट हो जाते हैं। वनों का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है। यह देखा गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जंगल की आग को मॉनिटर करने के लिए भारत में 2004 से शुरू सेटेलाइट की रिमोट सेंसिंग मोडिस अर्थात मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सेंसर और 2017 से भारतीय सेटेलाइट से सम्पूर्ण भारत में एसएनपीपी–वीआईआईआरएस अर्थात सुओमी–नेशनल पोलर आर्बिटिंग पार्टनरशिप–विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट के साथ जीआईएस टूल्स की मदद से वनों की आग को मॉनिटर किया जा रहा है। देश का कुल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है। नवीनतम आईएसएफआर 2021 के अनुसार देश का कुल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत है। वन सर्वे ऑफ इंडिया का अनुमान है कि देश में 36 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र में बार–बार आग लगती रहती है। देश के करीब 4 प्रतिशत वन क्षेत्र में अधिक तो 6 प्रतिशत भाग में सबसे अधिक खतरा पाया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वाच के अनुसार विश्व स्तर पर आग से वर्ष 2001 से 2022 के बीच 126 मिलियन हेक्टेयर वनों का नुकसान हुआ। इनमें वर्ष 2016 ऐसा वर्ष रहा जिसमें आग से सबसे अधिक 9.63 मिलियन हेक्टेयर वन आवरण का नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों में आग की घटनाओं को देखें तो 2001 से 2022 के बीच भारत में आग की घटनाओं से 35.9 हेक्टेयर वृक्ष आवरण को नुकसान और 2.15 मेगा हेक्टेयर वृक्ष आवरण का नुकसान अन्य कारणों से हुआ। इसमें भी 2008 में आग से सबसे अधिक कुल 3.5 प्रतिशत वृक्ष आवरण का नुकसान हुआ। अगर 12 अप्रैल 2021 से 8 अप्रैल 2024 के बीच आज की घटनाओं की बात की जाए तो 5,29,248 ड्कद्ढद्ढक्रस् के माध्यम से बड़ी आज की घटनाएं रिपोर्ट की गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष करीब 7 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र आग लगने की घटनाओं से प्रभावित होता है। इससे बड़े स्तर पर पर्यावरणीय और आर्थिक क्षति होती है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार विश्व में सन 2010 में 3.92 गीगा हेक्टेयर वृक्ष आवरण था जो पृथ्वी के 30 प्रतिशत से अधिक भू–भाग में फैला हुआ था, लेकिन 2023 में विभिन्न कारणों से 28.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण कम हो गया। सन 2001 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर 488 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण की हानि हुई जो 2000 के बाद से वृक्ष आवरण में 12 प्रतिशत की कमी के बराबर है, जबकि सन 2002 से 2023 के बीच कुल 76.3 मिलियन हेक्टेयर आद्र प्राथमिक वन कम हो गया। भारत की बात करें तो सन 2010 में 31.3 मिलियन हेक्टर प्राकृतिक वन थे जो कि इसकी कुल भूमि का 11 फीसद था, लेकिन वर्ष 2023 में 134 किलो हेक्टेयर आद्र प्राकृतिक वन की हानि हो गई। वर्ष 2002 से 2023 के बीच भारत में 414 हेक्टेयर आद्र प्राथमिक वन खो दिए।

ट्रंप और नेतन्याहू की नीतियों से परेशान दुनिया

विकास

लेबनान पर इजरायल के हमले ने पश्चिम एशिया में हालात और बिगाड़ दिए हैं। इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के बढ़ते युद्धोन्माद को अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सही ठहराते आए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने भस्मासुर खड़ा करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। हम नहीं जानते कि ट्रंप ने भस्मासुर जैसी कोई कहानी कभी सुनी है या नहीं, लेकिन अपने लंबे जीवन अनुभव से उन्होंने इतना तो सीखा ही होगा कि बुराई का फल बुराई के रूप में ही वापस मिलता है। दरअसल लेबनान पर इजरायल के हमले रुक ही नहीं रहे हैं, हाल ही में इजरायल ने लेबनान के दहिये और बेरूत पर बमबारी करने की धमकी दी है और वहां के निवासियों के लिए इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की है। इस पर ईरान ने भी कहा है कि इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही इजरायल के उत्तरी इलाके पर पलटवार करने का इरादा जताते हुए वहां के निवासियों को बचने के लिए सुरक्षित स्थान जाने की सलाह दी है। ईरान ने अमेरिका से जब पहली बार अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति दी थी तो उसकी शर्तों में लेबनान पर इजरायल के हमले रोकना भी शामिल था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को खबर आई कि ट्रंप ने फोन कॉल पर ही नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि, श्तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज की तारीख में हर कोई तुमसे नफरत करता है ।श बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने इजरायल को लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमलों को तुरंत रोकने के लिए कड़ा दबाव बनाया। जिसके बाद इजरायल बेरूत में अपने सैन्य कदम रोकने के लिए राजी हुआ है ।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नेतन्याहू पर किस किस्म का दबाव ट्रंप बना सकते हैं, क्योंकि दावा तो यही है कि नेतन्याहू एपस्टीन फाइल्स के नाम पर ट्रंप को दबाव में रखे हुए हैं। हालांकि नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी हैं, और उन के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, कई देशों में उनके जाने पर प्रतिबंध है, तो मुमकिन है ट्रंप ने उन पर ऐसा ही कोई दबाव बनाया हो। बता दें कि नेतन्याहू को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 21 नवंबर 2024 को युद्ध अपराधी घोषित कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन वारंट्स में उन पर गजा में युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का उपयोग करने और नागरिकों पर जानबूझ कर हमले करने जैसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं ।बहरहाल, ट्रंप और नेतन्याहू में से किसने, किस पर, कौन सा दबाव बनाया, इसका खुलासा तो शायद ही कभी हो, लेकिन इन दोनों की युद्धपिपासु प्रवृत्ति ने पूरी दुनिया को बड़ी तबाही की तरफ धकेल दिया है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान को मजबूरन होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग बंद करना पड़ा, ताकि दुनिया में तेल की आपूर्ति बाधित हो तो इन दोनों देशों को युद्ध की कीमत चुकाने का अहसास हो। हालांकि वेनेजुएला के तेलस्रोतों पर कब्जा करके या रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाकर अमेरिका अब तक अपनी दादागिरी को चला रहा है। लेकिन अब उसकी जिद भी कहीं न कहीं टूट रही है। ट्रंप जाहिर तौर पर तो ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कभी अस्थायी युद्धविराम, इस्लामाबाद शांति वार्ता आदि के अलावा अन्य तरीकों से भी समझौतों की कोशिश में लगे हैं। ईरान पर युद्ध में अमेरिका को जितना आर्थिक और सामरिक नुकसान हुआ है, उससे अपने ही देश में ट्रंप घिर चुके हैं। ऐसे में इजरायल की बेवजह आक्रामकता से ईरान के साथ क्षेत्रीय शांति स्थापित करने की अमेरिका की पूरी कूटनीति दांव पर लग गई है, यह ट्रंप समझ रहे हैं। लेबनान पर इजरायल के हमलों के विरोध में ईरान ने ओमान और अन्य माध्यमों से अमेरिका के साथ चल रही अपनी परोक्ष शांति वार्ता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ी मीडिया एजेंसी श्तस्नीमश ने साफ किया है कि जब तक लेबनान और गजा में इजरायल के हमले पूरी तरह नहीं रुकते और ईरान के सहयोगियों के हितों की रक्षा नहीं होती, तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने दो टूक कहा है कि – श्एक मोर्चे पर युद्धविराम का उल्लंघन, सभी मोर्चों पर युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा ।श्इसके अलावा ईरान अपने सहयोगी यमन के हूती समूह के जरिए बाब अल–मंदाब समुद्री रास्ते को भी बंद करने की चेतावनी दी है। होर्मुज के बाद अगर बाब अल–मंदाब भी बंद हुआ तो दुनिया अकल्पनीय नुकसान में पड़ जाएगी। यमन (एशिया) और जिबूती–इरिट्रिया (अफ्रीका) के बीच स्थित यह जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और आगे स्वेज नहर तक जाता है। इस संकरे रास्ते से दुनिया के कुल समुद्री व्यापार के करीब 30 प्रतिशत कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं। खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका जाने वाला रोजाना 40 से 70 लाख बैरल कच्चा तेल और

लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी मार्ग से भेजा जाता है। अगर ईरान और हूती ने इस रास्ते को बाधित कर दिया, तो जहाजों को अफ्रीका के श्केप ऑफ गुड होपश से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा का समय 10 से 14 दिन बढ़ जाएगा, माल ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्च बेतहाशा बढ़ेगा और पूरी दुनिया में भयानक महंगाई आ जाएगी ।इस वक्त वैसे ही ऊर्जा का वैश्विक संकट कायम है, जिससे त्राहि–त्राहि मची है। अब बाब अल–मंदाब भी अगर बाधित होता है तो तय है कि इजरायल और अमेरिका के कारण केवल पश्चिम एशिया में तबाही नहीं मचेगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और सबसे बढ़कर अहम समुद्री मार्ग पूरी तरह तहस–नहस हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नेतन्याहू को दी गई चेतावनी इसी आने वाली बड़ी तबाही का डर है ।अमेरिका और इजरायल की आक्रामक नीतियों और कार्रवाइयों पर रूस, चीन के साथ यूरोप, अफ्रीका के कई देश आलोचना कर रहे हैं और ईरान के साथ शांति वार्ता कामयाब होने के पक्षधर हैं। लेकिन भारत इस मामले में अपना स्पष्ट रूख रखने में बार–बार कतरा रहा है। खासकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नरेन्द्र मोदी की नजदीकियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे संकेत नहीं दे रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सही सवाल किया है कि– दुनिया के कई देश इजरायल की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी वास्तविक मातृभूमि (भारत) से ज्यादा उनकी तथाकथित पितृभूमि (फादरलैंड) मायने रखती है।

जौनपुर में गैस लीक से पांच झुलसे रेगुलेटर बदलते समय हादसा, अस्पताल में भर्ती

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के शिवापार गांव में गुरुवार दोपहर रसोई गैस लीक होने से एक ही परिवार के पांच सदस्य झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में बिजेंद्र यादव (38), उनकी पत्नी अनीता (35), बेटियां वर्तिका (11) और कृतिका (14), तथा बेटा श्रेयांश (8) शामिल हैं। यह सभी घटना के समय रसोईघर में मौजूद थे। बिजेंद्र यादव रसोईघर में गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बदल रहे थे। इसी दौरान गैस लीक हो गई। जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, लीक हुई गैस ने आग पकड़ ली, जिससे परिवार के पांचों सदस्य झुलस गए। आशंका है कि गैस पहले से ही लीक हो रही थी। घटना के बाद, आनन–फानन में परिवार के सदस्यों को निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है।सभी की हालात स्थिर है।कोई जानमाल की हानि नहीं है।वही इस मामले में थानाध्यक्ष लाइन बाजार ने बताया घायलों को हॉस्पिटल में उपचार के लिय भर्ती कराया गया है सभी ठीक है।घर में से सिलेंडर हटा दिया गया है।

गैंगस्टर मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर को हाईकोर्ट से राहत

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बलरामपुर के पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर और उनके दामाद रमीज नेमत को

बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट, ट्रायल कोर्ट के संज्ञान और समन आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट लगाने से पहले कानून में तय जरूरी शर्तों का सही ढंग से पालन नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होना ही गैंगस्टर एक्ट लगाने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। तुलसीपुर थाने में 2024 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पुलिस ने रमीज नेमत को गिरोह का सरगना और रिजवान जहीर को सदस्य बताया था। गैंग चार्ट में दो आपराधिक मामलों को आधार बनाया गया था। इनमें एक मुकदमे में दोनों के नाम थे, जबकि दूसरे हत्या के मामले में केवल रमीज नेमत आरोपी थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी पाया। जिस थाना प्रभारी ने 7 जुलाई 2024 को गैंग चार्ट तैयार किया था, उसी अधिकारी ने बाद में एफआईआर में लिखा कि उसे 20 जुलाई 2024 को गश्त के दौरान गिरोह की जानकारी मिली। अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय माना। हाईकोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट तभी लगाया जा सकता है, जब यह साबित हो कि आरोपी सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने या अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध कर रहे थे। मामले में ऐसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। अदालत ने यह भी माना कि जांच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और ट्रायल कोर्ट ने जरूरी कानूनी संतुष्टि दर्ज किए बिना कार्रवाई आगे बढ़ाई। इसी आधार पर कोर्ट ने चार्जशीट और समन आदेश रद्द कर दिए।

30 जून तक चलेगा पीएम स्वनिधि विशेष अभियान, स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत जनपद में 1 जून से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। परियोजना अधिकारी डूडा निधि बाजपेयी ने बताया कि अभियान के दौरान जनपद स्तर पर स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों की सफलता की कहानियां साझा की जाएंगी। नगर निकाय स्तर पर लोक कल्याण मेले, बैंकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स की बैठकें भी आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों में वेंडर्स को ऋण, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी नगर निकायों के साथ–साथ सेंसस टाउन क्षेत्रों में भी विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में नए स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम जनधन योजना, वन नेशन–वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृ वंदना योजना तथा श्रम विभाग में पंजीकरण जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इस बीच शासन ने योजना का विस्तार करते हुए जलालपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत महिमापुर को सेंसस टाउन के रूप में शामिल किया है। अब यहां के ठेला, खोमचा और रेहड़ी–पटरी व्यवसायियों को भी बिना गारंटी के 15 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शहर मिशन प्रबंधक डूडा जौनपुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस पहल से छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

सिपाही की बगावत ने खोला भ्रष्टाचार का खेल, सिर मुड़ाते ही पड़े ओले, नई ताजपोशी से खलबली

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में एक बागी सिपाही ने अब तक ढके–छिपे हो रहे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर कर दिया है तो प्रदेश के कई विभागों में तबादले के बाद एक साहब जिससे परेशान थे वही वरिष्ठ अब उनके सीनियर बनकर आ गए। ऐसे में साहब बड़े परेशान हैं। वहीं, प्रदेश में खाकी के मुखिया की नई ताजपोशी होने के बाद अपने नंबर बढ़वाने की होड़ लग गई है। बीते दिनों एक सिपाही ने बगावत कर दी। ये बगावत भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। उसने सबूतों के साथ पुलिस लाइनों में हो रहे खेल को उजागर किया था। ये किसी एक पुलिस लाइन की कहानी नहीं बल्कि ये एक उदाहरण मात्र था। अब बागी सिपाही के आरोप सही होते जा रहे हैं। गंगा किनारे वाले कमिश्नरेट में ऐसे ही भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हुआ है। जांच की आंच कई बड़े जिम्मेदारों तक भी पहुंच रही है। देखना ये है कि इसमें छोटी मछलियों का शिकार होगा या बड़े जिम्मेदार भी नपेंगे।

प्रदेश में हाल ही में तबादला एक्सप्रेस काफी तेजी से चली। इसमें प्रदेश के पढ़ाई–लिखाई वाले विभाग के काफी समय से परेशान अधिकारी ने भी काफी मशक्कत से अपने तबादले में सफलता पाई। वह अपने एक वरिष्ठ से काफी परेशान थे लेकिन विभाग में जब बड़े अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ तो वह ठगा से महसूस कर रहे थे। जिन साहब से वह परेशान थे, वही उनके मुखिया बनकर आ गए। अब विभाग में यह चर्चा आम है कि उन पर तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब वह बड़े साहब के साथ कैसे तालमेल बैठाएंगे? खाकी वाले विभाग में आजकल खासी खलबली मची है। पुराने मुखिया की नई ताजपोशी होने के साथ उन अफसरों की शामत आनी तय मानी जा रही है जो हाईकमान की नाराजगी का सबब बन चुके हैं। इस बीच एक साहब प्रमोशन के बाद अपने नंबर बढ़ाने में जरा भी नहीं चूके और गुलदस्ता लेकर हाईकमान के पास धमक पड़े। इसकी फोटो भी वायरल हो गई। हालांकि, साहब के सेवा के दिन कम बचे हैं। विभाग में चर्चा है कि इतना मिलने के बाद भी आखिर क्या बाकी है जो जाते–जाते चाहिए।

जौनपुर में दो क्षेत्राधिकारियों का तबादला

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पुलिस विभाग में गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने जिले के दो पुलिस उपाधीक्षकों (सीओ) का तबादला अन्य जनपदों में किया, जबकि दो नए अधिकारियों को जौनपुर में तैनात किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, शाहजहांपुर में तैनात पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार राय को जौनपुर भेजा गया है। इसी तरह, बागपत से विजय कुमार चौधरी को भी जौनपुर में नई तैनाती मिली है। इन दोनों अधिकारियों को जल्द ही जिले में सर्किल का प्रभार सौंपा जाएगा। लंबे समय से जौनपुर में तैनात दो सीओ का भी तबादला किया गया है। सीओ अजीत सिंह चौहान, जिन्हें हाल ही में शाहगंज से केराकत की कमान सौंपी गई थी, अब केराकत से चंदौली स्थानांतरित किए गए हैं। वहीं, करीब तीन साल से जौनपुर में तैनात सीओ सदर देवेश सिंह को बरेली भेजा गया है। यह तबादले शासन की स्थानांतरण नीति के तहत हुए हैं। इस नीति के तहत तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों को हटाया जा रहा है। त्योहारों के सीजन से पहले कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से भी यह बदलाव किए गए हैं।इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह ने बताया कि शासन से आदेश प्राप्त हो गया है। नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करते ही उन्हें सर्किल का चार्ज दिया जाएगा। उन्होंने इसे एक नियमित प्रक्रिया बताया और कहा कि सभी अधिकारियों ने जौनपुर में अच्छा काम किया है। जिले में एक साथ दो नए सीओ के आने और दो पुराने अधिकारियों के जाने से पुलिस महकमे में हलचल है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नए अधिकारी जिले की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे।

यूपीपीसीएल के पेंशनरों को तोहफा, महंगाई राहत बढ़कर 60 प्रतिशत हुई

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) एवं उसकी सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा। कॉरपोरेशन ने 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही महंगाई राहत की कुल दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।यूपीपीसीएल के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा 21 मई 2026 को जारी शासनादेश के अनुरूप लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत प्रदान करने की स्वीकृति दी थी, जिसके क्रम में पावर कॉरपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों तथा केस्को के पेंशनरों को भी समान लाभ दिया गया है।

दहेज हत्या के मामले में वांछित पति गिरफ्तार, ट्रॉमा सेंटर से दबोचा गया आरोपी

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सआदतगंज पुलिस ने दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी पत्नी की कथित दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहा था और ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद शहर छोड़कर भागने की फिराक में था।पुलिस के अनुसार सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला और प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर ट्रॉमा सेंटर, केजीएमयू से सागर लोधी (29) निवासी सुल्तानपुर गढ़ैया, थाना सआदतगंज को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त खबरें

बर्थडे पार्टी की बुकिंग बनी साजिश

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के इटौंजा क्षेत्र में अपराधियों ने एक फोटोग्राफर को जन्मदिन समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का झांसा देकर सुनियोजित तरीके से लूट का शिकार बना दिया। बदमाशों ने पहले कार्यक्रम की बुकिंग के नाम पर संपर्क किया, फिर सुनसान स्थान पर बुलाकर उसकी कार रोक ली और लाखों रुपये मूल्य के कैमरे, लेंस, गिम्बल तथा मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दावा किया है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है।पुलिस के अनुसार ग्राम रानीखेड़ा, थाना माल निवासी अशोक यादव, जो पेशे से फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर हैं, ने मंगलवार को थाना इटौंजा पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनसे संपर्क कर जन्मदिन समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की बात कही थी। कार्यक्रम के लिए उन्हें 1 जून की रात लगभग साढ़े आठ बजे नीलांश वाटर पार्क रोड के पास बुलाया गया।अशोक यादव के अनुसार जब वह अपने उपकरणों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवकों ने उनकी कार को घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें धमकाया और उनके पास मौजूद महंगे फोटोग्राफी उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। वारदात के दौरान विरोध करने पर उन्हें भयभीत किया गया, जिसके बाद आरोपी आराम से सामान लेकर मौके से फरार हो गए।पीड़ित के अनुसार लूटे गए सामान में छह पेशेवर कैमरे, सात लेंस, दो गिम्बल और एक मोबाइल फोन शामिल हैं।

त्रिवेणी इंजीनियरिंग को 4.05 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि मंजूर

लखनऊ, (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाई मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 4.05 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर दी है। इस राशि का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में किया जाएगा।औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार कंपनी को अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कुल 4 करोड़ 4 लाख 47 हजार 54 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी को देय प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 59 हजार रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 4 करोड़ 5 लाख 6 हजार 54 रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।प्रदेश सरकार का मानना है कि औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि होने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दे रही है।

कॉपी जांचने के लिए शिक्षकों को नहीं लगानी होगी दौड़

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज के शिक्षकों को अब कॉपी जांचने के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी। अगले सत्र से शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए लविवि डिजिटल मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। लविवि में मंगलवार को कुलपति की लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (लुआक्टा) के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। लविवि कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि डिजिटल मूल्यांकन की व्यवस्था शुरू होने पर कॉपियों को स्कैन किया जाएगा। इससे न तो कॉपियों को एक से दूसरे स्थान ले जाना पड़ेगा और ना ही शिक्षकों को मूल्यांकन केंद्र तक दौड़ लगानी होगी। ऐसा होने पर शिक्षकों का समय बचेगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। इसकी विशेषता यह भी होगी कि मूल्यांकन करते ही शिक्षकों के खाते में पोर्टल के माध्यम से पारिश्रमिक भी आ जाएगा। बैठक में लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय, महामंत्री डॉ. अंशु केडिया सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि विश्वविद्यालय जल्द ही एक खेल परिषद का गठन करेगा। इस परिषद का उद्देश्य खेल गतिविधियों को संस्थागत रूप देना और छात्रों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले सत्र से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को अंशकालिक पीएचडी करने की अनुमति दी जाएगी। संबद्ध महाविद्यालयों को शोध केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसके मानक निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इससे महाविद्यालय भी शैक्षणिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।

संगीत–नृत्य के शोधार्थियों को आर्थिक संबल

लखनऊ, (संवाददाता)। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के तहत शोधार्थियों को फेलोशिप उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पंजीकृत जेआरएफ–उत्तीर्ण पीएचडी शोधार्थी अब फेलोशिप का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। फेलोशिप की सुविधा मिलने से शोधार्थियों को आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे वे अपने शोध कार्य को अधिक गंभीरता, गुणवत्ता और समर्पण

के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यूजीसी ने इसके लिए आवश्यक यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिए हैं। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को नई गति देने के साथ अकादमिक उत्कृष्टता को भी मजबूत करेगी। विश्वविद्यालय का मानना है कि इस पहल से संगीत, नृत्य, ललित कला और संस्कृति से जुड़े शोध कार्यों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा। कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह शोधार्थियों के लिए नई ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट तथा नवोन्मेषी शोध प्रस्तुत करेंगे।

गणित ने उलझाया, रासायनिक सूत्र बने सहारा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी सहित प्रदेश के 163 केंद्रों पर मंगलवार से शुरू हुई पॉलीटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को गणित के प्रश्नों ने सबसे ज्यादा उलझाया। रासायनिक सूत्रों से जुड़े सवालों ने उन्हें राहत दी। तीन पालियों में आयोजित परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को लेकर मिली–जुली प्रतिक्रिया दी। चिनहट स्थित एक परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर निकले शैलेश कुमार ने बताया कि दो घंटे की परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों को हल करना था। इनमें 50 प्रश्न गणित से, जबकि 25–25 प्रश्न रसायन और भौतिक विज्ञान से पूछे गए। ज्यादातर प्रश्न हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पर आधारित थे। गणित के कई प्रश्नों के पैराग्राफ बड़े थे, जिन्हें समझने में कठिनाई हुई। रासायनिक सूत्रों से जुड़े प्रश्न अपेक्षाकृत आसान रहे। अभ्यर्थी मो. अयान ने बताया कि वह पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए। शुरुआत में कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्नों को समझने में परेशानी हुई और लगभग 20 मिनट इसी में लग गए। इसके बाद उन्होंने प्रश्नों को हल करना शुरू किया। हालांकि निर्धारित समय समाप्त होने से पहले ही उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (पॉलीटेक्निक) के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी सहित प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 163 केंद्रों पर तीन पालियों में परीक्षा हुई। इनमें पंजीकृत 64659 में से 50331 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहले दिन इस परीक्षा में कुल 77.84 प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। नौ जून तक परीक्षा आयोजित होगी।

लविवि में छात्रों के निष्कासन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना

लखनऊ, (संवाददाता)। कुलपति कार्यालय के बाहर 28 अप्रैल को प्रदर्शन करने के आरोप में सोमवार को निष्कासित किए गए तीन छात्रों के समर्थन में छात्र संगठन मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की और निष्कासन वापस लेने की मांग करते रहे। देर रात तक विवि प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि छात्रों से मुलाकात करने नहीं पहुंचा था। पुलिस बल की मौजूदगी में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। निष्कासित छात्रों में एमए हिंदी प्रथम वर्ष के प्रेम प्रकाश यादव, एमए लोक प्रशासन प्रथम वर्ष के शशि प्रकाश और एलएलबी (त्रिवर्षीय) द्वितीय सेमेस्टर के हर्षित शुक्ला शामिल हैं। तीनों छात्र पहले से निलंबित चल रहे थे। विवि प्रशासन के अनुसार, घटना की जांच कुलानुशासक मंडल ने की थी। मंडल ने 21 मई को रिपोर्ट सौंपी, जिस पर कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने 25 मई को सहमति दी। कुलपति के आदेश पर निष्कासन की कार्रवाई की गई। आदेश में कहा गया है कि तीनों छात्रों को भविष्य में विवि के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही उनका विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस घटना से आक्रोशित छात्रों ने विवि के गेट नंबर एक पर मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की और और कुलपति समेत अन्य अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि निष्कासन का फैसला वापस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तीनों छात्र नेताओं का निष्कासन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। छात्रहितों की बात करने पर की गई निलंबन और अर्थदंड की कार्रवाई रद्द की जाए। विश्वविद्यालय में की गई फीस वृद्धि वापस ली जाए और छात्रसंघ चुनाव बहाल किए जाएं। विश्वविद्यालय परिसर में डेरा डाले बैठे पुलिसकर्मियों को हटाया जाए।

दो महीने से वेतन नहीं मिलने पर पीसीएस अधिकारियों में नाराजगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात अनेक प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों को पिछले दो महीनों से वेतन न मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पीसीएस (प्रोन्नत) अधिकारी संघ ने शासन को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि नियुक्ति अनुभाग–11 द्वारा समय से वेतन पर्चियां जारी न किए जाने के कारण अप्रैल और मई माह का वेतन आहरित नहीं हो सका है, जिससे अधिकारियों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।संघ के अध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश के कई जनपदों में कार्यरत पीसीएस अधिकारियों को लगातार दो माह से वेतन नहीं मिला है। संघ के संज्ञान में आए मामलों के अनुसार वेतन भुगतान में देरी का मुख्य कारण नियुक्ति अनुभाग–11 द्वारा संबंधित अधिकारियों की वेतन पर्चियां समय पर जारी न किया जाना है। वेतन पर्ची के अभाव में कोषागार से वेतन का आहरण संभव नहीं हो पा रहा है।संघ ने अपने पत्र में कहा है कि लगातार दो महीने तक वेतन न मिलने से अधिकारियों को अपने पारिवारिक खर्चों के संचालन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा, गृह ऋण और अन्य ऋणों की मासिक किश्तों के भुगतान, चिकित्सा व्यय तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे अधिकारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ–साथ मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो रहा है।पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारी फील्ड और सचिवालय स्तर पर पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

'डीएम की अध्यक्षता में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण कार्य की बैठक संपन्न'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' बुधवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों के संबंध में वीसी कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देश दिए निर्माण कार्यों में तेजी लाकर जल्द से जल्द गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण भी किया जाए। जिलाधिकारी ने ट्रामा सेंटर एवं इमरजेंसी के रिनोवेशन का कार्य 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज में सीसी रोड, नाली आदि कार्य जल्द कर लिए जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज के सामने अनावश्यक खड़े होने वाले वाहनों एवं ठेलों को व्यवस्थित किया जाए। मेडिकल कॉलेज के अंदर एवं बाहर अच्छे से साफ सफाई प्रतिदिन की जाएध सभी कार्यों के लिए अलग–अलग नोडल अधिकारी बनाया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज में अच्छी वॉल पेंटिंग, खाली जगह पर पार्क, क्यारियां, गमले, वार्ड, कैंटीन को जाने के लिए साइनेज लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए मिलने वाले ब्रेकफास्ट, लंच आदि के मेनू का भी बोर्ड लगाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट गेटवे से लिंक कराया जाए और क्यूआर कोड प्रत्येक गांव में लगाएं जिससे मेडिकल कॉलेज में उपचार करने के लिए लोग स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकें। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन एवं दवा वितरण के अतिरिक्त काउंटर चलाने की व्यवस्था की जाए। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को तत्काल उपचार मिलना सुनिश्चित कराया जाए। मरीजों एवं तीमारदारों से अच्छा व्यवहार किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज आने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के पास जारी किए जाएं वही लोग वाहन लेकर अंदर जाएंगे। उनके वाहन खड़े करने की व्यवस्था की जाए इसके अलावा कोई भी वाहन अंदर नहीं जाना चाहिए। मुख्य द्वार से अनावश्यक वाहनों को अंदर न आने दिया जाए इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को अंदर और बाहर से साफ सुथरा एवं सुंदर बनाना है। उन्होंने कहा कि चयन कर दीवारों की वॉल पेंटिंग कर उस परअच्छे–अच्छे संदेशो को लिखवाया जाए। जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने एवं बाहर सड़क, नाली सही कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर लिए जाए। इस अवसर पर नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी एवं प्रधानाचार्य डॉ राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

दिल्ली अग्निकांड के बाद एक बार फिर जागा अग्निशमन विभाग

अयोध्या। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे नाम के नाम एक होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत से आखिरकार फायर विभाग जागा।देखा जाए वर्ष 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शहर के अधिकतर होटल तथा रेस्टोरेंट के अलावा भारी संख्या में गली कूचों मोहल्ले तथा कॉलोनी को गेस्ट हाउस खुले। देखा जाए तो गेस्ट हाउस तथा रेस्टोरेंट होटल मानक पर खड़े नहीं उतर रहे बीच–बीच में जब कोई आसपास के जिलों या फिर अयोध्या में अप्रिय घटना होती है तब पुलिस, अग्निशमन विभाग विकास प्राधिकरण एक बार फिर कुंभकर्णी नींद से जाग कर इन पर कार्यवाही करता तो है लेकिन एक–दो दिन बाद मामला ठंडा बस्ती में चला जाता है। इसी तरह बुधवार को सुबह दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक गली में फ्लरिश रेस्टोरेंट में अचानक लगी आग से 21 लोगों की आज सामाजिक मौत हो गई देखा जाए इसमें सबसे बड़ी कमी उक्त रेस्टोरेंट में बेसमेंट के नीचे बने किचन में आग लगने से यह घटना हुई इसी तरह रामनगरी में कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट पेइंग गेस्ट हाउस हैं जिनके किचन बेसमेंट में है और यहां देखा जाए वह मानक पर भी खड़े नहीं उतर रहे प्राण प्रतिष्ठा हुई

2 वर्ष से अधिक हो गया लेकिन आज तक इन पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी चाहे फायर विभाग से जुड़े हो विकास प्राधिकरण से जुड़े हूं यह फिर पुलिस प्रशासन से शिकंजा कसने की जहमत नहीं उठाई हां इतना जरूर है दिल्ली जैसे अन्य जगहों पर जब किसी तरीके की घटना होती है तब यहां का प्रशासन एक बार फिर जग जाता है यह ठीक इसी तरह आज दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए फायर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने शहर के नामी ग्रामीण होटल में तथा रेस्टोरेंट पर जाकर निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति कर लिया बताते चले बुधवार को सुबह सिविल लाइन स्थित होटल रेडियस के अलावा अन्य प्रमुख नामी ग्रामीण होटल में जाकर यह खानापूर्ति अग्नि सम्मान विभाग के कर्मियों ने किया।इसका नेतृत्व कर रहे प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने होटल में तैनात अधिकारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को अग्नि शमन यंत्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया साथ ही साथ वहां पर मार्क ड्रिल किया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने बताया की दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए यहां पर होटल पर जाकर सभी लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी जा रही है। मानक पर खड़े न उतरने वाले होटल तथा गेस्ट हाउस के बारे में उन्होंने कहा की उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हुए आने वाले दिनों में चेकिंग अभियान चलाएंगे।

संतोष कुमार सिंह जिला पंचायत के बने अपर मुख्य अधिकारी,सम्भाला कार्यभार

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिला पंचायत अयोध्या के अपर मुख्य अधिकारी के रूप में संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया श्री सिंह इससे पहले शासन में संबंद्ध थे।जिला पंचायत कार्यालय पहुंचने पर कार्य अधि

ाकारीध प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी अधिकारी चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने अंग वस्त्र व बुके प्रदान कर नवागत अपर मुख्य अधिकारी का स्वागत किया।इस दौरान मोहम्मद फैसल, विजय कुमार, बृजेश कुमार, अशोक कुमार चौधरी, विकास मिश्रा, भोले पाल सहित अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर के साथ महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या। गुरुवार को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौड़ के साथ जिला महिला अस्पताल ,जिला पुरुष चिकित्सालय, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया है।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व

सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।इस मौके पर महिला कांस्टेबल वंदना यादव,रिक्रूट महिला कांस्टेबल लक्ष्मी सोनी मौजूद रहे।

लोक जनशक्तिपार्टी के प्रदेश महासचिव चौधरी अरुण कुमार कोरी ने पार्टी से दिया इस्तीफा

अयोध्या।चौधरी अरुण कुमार कोरी ने अपने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महासचिव थे जिन्होंने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपने सीनियर लीडरों को इस्तीफा भेज दिया है उन्होंने कहा कि जन विरोधी नीतियों के कारण मैं पार्टी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच रहा और जनता के लिए ही लड़ाई लड़ा हूं लेकिन मुझे यह लग रहा था कि अब जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है जिससे आहत होकर मैं यह निर्णय लिया और पार्टी से और पद से इस्तीफा दे दिया है।चौधरी अरुण कुमार के इस्तीफा के बाद उन्होंने लोकप्रिय समाज पार्टी (एल. एस .पी.)ज्वाइन की है जहां उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उन्होंने कहा कि मैं जनता की लड़ाई नहीं छोड़ सकता और मैं जहां रहूंगा गरीबों की मजलूमों की लड़ाई लड़ता रहूंगा उन्होंने लोकप्रिय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद अदा किया चौधरी अरुण कुमार कोरी के लोकप्रिय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोगों में खुशी की लहर है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनको बधाई देने का सिलसिला चल पड़ा है बधाई देने वालों में अवधेश कुमार एडवोकेट.मोहम्मद अतीक अहमद एडवोकेट .ओमप्रकाश कोरी एडवोकेट .शालिग्राम सुधाकर एडवोकेट.गंगाराम वर्मा .पवन कुमार निगम एडवोकेट .आसाराम यादव. राकेश मौर्या .उधम सिंह .सुमित कोरी .राम सिंह.राजकुमार एडवोकेट. सहाबुद्दीन कोरी.नंदू पासवान.सुमित कनौजिया.राकेश कुमार चौधरी .कृष्ण कुमार चौधरी एडवोकेट.लियाकत हुसैन .गोविंद कोरी .जाकिर हुसैन. शंकर श्रीवास्तव.सचिन पांडे .चंदन एडवोकेट.नीतू .सुशीला कोरी .श्रीमती सुजाता .सहित बड़ी संख्या में लोगों ने चौधरी अरुण कुमार कोरी को लोकप्रिय समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई है इन लोगों का कहना है कि चौधरी अरुण कुमार 40 साल से राजनीति के क्षेत्र में है उन्होंने हमेशा गरीब मजलूम असहाय लोगों की समस्याओं को उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस पार्टी का नेतृत्व मिला है तो यहां भी वह गरीब मजलूम असहाय लोगों की आवाज बनेंगे अगर हम चौधरी अरुण कुमार कोरी की बात करें तो उन्होंने 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा है 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है वह बीएसपी और लोक जनशक्ति पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और अब लोग प्रिय समाज पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में करेंगे और और अपनी राजनीतिक जीवन की एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं

विश्व पर्यावरण दिवस पर अयोध्या में होगा 5.63 लाख पौधों का रोपण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जनपद अयोध्या में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।इस दौरान जिले में कुल 5 लाख 63 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा। यह अभियान प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।प्रभागीय वनाधिकारी अयोध्या वन प्रभाग प्रखर गुप्ता ने बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार प्रदेश में 5 करोड़ पौधे रोपित किए जाने हैं। इसी क्रम में अयोध्या जनपद को 5.63 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।उन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।अभियान के तहत सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों तथा आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य आयोजन पंचवटी दीप पर होगा,जहां प्रदेश के प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ करेंगे।इस अवसर पर जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी,वन विभाग के अधिकारी–कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहेंगे।वन विभाग ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। विभाग का कहना है कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का भी प्रभावी माध्यम है।

नगर निगम अयोध्या में वेतन से कटौती किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने आज भी जारी रखी हड़ताल

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। अयोध्या धाम के पन्द्रह वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रह करने वाले कर्मचारियों ने इसका ठेका लेने वाली ओम् स्वच्छता कम्पनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके अन्तर्गत आज तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। कोई भी कूड़ा संग्रहक क्षेत्र में घरों से कूड़ा एकत्र करने नहीं गया बल्कि नलकूप 04 के परिसर में पूरे समय हड़ताल पर बैठे रहे जिससे आज तीसरे दिन या तो घरों में कूड़ा डस्टबिन में रखा रहा रहा या तो गृह स्वामी ने घर का एकत्र कूड़ा पास पड़ोस की खाली जमीन पर फेंक दिया।ओम स्वच्छता कम्पनी के मातहत काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वैसे ही कम्पनी द्वारा वेतन हम लोगों को कम दिया जा रहा है इसके बाद हर महीने अकारण भारी कटौती कर दी जा रही है।सात हजार रुपए में हमारे घर का खर्च कैसे चल सकता है? हमें सरकार द्वारा निर्धारित मनरेगा का भी पैसा हर माह नहीं दिया जा रहा है। कूड़ा ढोने वाले ठेले खराब हो जाने पर उन्हें हमें अपनी जेब से खर्च कर ठीक कराने पड़ता है कम्पनी इस जिम्मेदारी को भी नहीं निभाती है। कूड़ा संकलित करने वाले टूटे डस्टबिनों को भी कम्पनी नहीं बदलवा रही है जिसके कारण तमाम कूड़ा सड़क पर जगह–जगह गिरता रहता है। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम अयोध्या के महापौर व अधिकारी गण कम्पनी से सांठगांठ करके हम गरीबों का शोषण कर रहे हैं। कई बार हम लोग अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है लेकिन हमारी बात कम्पनी के लोगों के साथ–साथ अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। यदि हमारी इन समस्याओं का निराकरण कराने के साथ–साथ कटौती किया धन धन हमारे खाते में न भेजा गया तो हम सब मजबूर हो कर सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। ओम स्वच्छता कंपनी की कार्य प्रणाली से आक्रोशित पार्षदों ने भी धरना–प्रदर्शन करके महापौर व नगर आयुक्त से कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।

वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ प्रो. राजीव रंजन उपाध्याय का निधन, शोक की लहर

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैंसर विशेषज्ञ एवं साहित्यकार प्रो. राजीव रंजन उपाध्याय का गुरुवार को 86 वर्ष की आयु में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से चिकित्सा, साहित्य और बौद्धिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को जमथरा घाट पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों, अधिवक्ताओं, साहित्यकारों तथा शुभचिंतकों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी।4 मार्च 1942 को जन्मे प्रो. राजीव रंजन उपाध्याय ने कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट

पहचान बनाई थी। वे ईरान, नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे देशों में कैंसर विज्ञान कथा लेखन के प्रोफेसर रहे तथा चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैंसर विज्ञान पर उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनेक पुस्तकों का लेखन किया, जिन्हें चिकित्सा जगत में व्यापक सराहना मिली।भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रो. उपाध्याय अखिल भारतीय विज्ञान कथा लेखन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार बद्री नारायण उपाध्याय 'प्रेमधन' के पौत्र थे। उनके निधन को चिकित्सा और साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। श्रद्धांजलि देने वालों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

निःशुल्क विद्युत चालित चाक मशीन आवेदन करे 15 जून तक

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अयोध्या ने बताया कि उ0प्र0 माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित माटीकला टूल किट्स (विद्युत चालित कुम्हारी चाक) वितरण कार्यक्रम योजनान्तर्गत कुम्हार/प्रजापति समाज के माटीकला के परम्परागत कुशल कारीगर शिल्पकार, शिक्षित बेरोजगार एवं राजस्व विभाग से मिट्टी निकालने हेतु प्राप्त पट्टा धारक शिल्पियोंध्कारीगरों के ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 जून तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक महिलाध्पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो, वे अपना आवेदन पत्र आधार कार्ड, शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण– पत्र, राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल व पासपोर्ट साइज फोटो के साथ विभागीय वेबसाइट www-upmatikalaboard-in पर योजनाओं के अन्तर्गत माटीकला टूल किट्स वितरण योजना पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उ०प्र० शासन द्वारा गठित चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा, जिसकी तिथि निर्धारित होने पर अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।साक्षात्कार में स्वयं भाग लेना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में प्रतिभाग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।जानकारी हेतु मो० नं०–9580503164, 9956128787 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

जून में नहीं होगी भीषण गर्मी,एक बार फिर सक्रिय होगा एक और विक्षोभ

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चार जून यानी बृहस्पतिवार से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है।इसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में गरज–चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट है पिछले दो दिनों से प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बुधवार को करीब 10 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा। बस्ती 42 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया। इसके अलावा फतेहपुर में 41.6 डिग्री, लखीमपुर खीरी में 41 डिग्री, झांसी में 40.6 डिग्री तथा वाराणसी और प्रयागराज में 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार चार जून से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन इसके प्रभाव से गुरुवार को पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, पांच और छह जून को इसका असर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों में भी आंधी और छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं।हालांकि तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है।इन जिलों में है गरज चमक व आंधी का येलो अलर्ट गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल व आस पास के क्षेत्र है।

लाइब्रेरी फीस वृद्धि से नाराज छात्रों ने नगर निगम घेरा

प्रयागराज, (संवाददाता)। रामबाग स्थित राजकीय जिला डिजिटल पुस्तकालय में छात्रों से प्रति माह 500 रूपए रखरखाव शुल्क वसूले जाने के विरोध में छात्रों ने नगर निगम का घेराव किया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2026 के आदेश से यह शुल्क अनिवार्य कर दिया। जबकि पुस्तकालय पहले निःशुल्क सेवा के तौर पर संचालित होता रहा। घेराव कर रहे छात्रों ने बताया कि अधिकारियों ने पहले पुस्तकालय को निःशुल्क रखने का आश्वासन दिया था। अब किसी निजी फर्म द्वारा बिना शासन की अनुमति भारी शुल्क वसूलना नियमों का उल्लंघन है। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे ग्रामीण व कमआय वाली पृष्ठभूमि से हैं और यह अचानक लगाया गया शुल्क आर्थिक और मानसिक बोझ बन गया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।

नाली और सड़क की बदहाली से जनता त्रस्त, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे प्रशासन – सरोज यादव

अयोध्या। बदहाल सड़क जाम नालियां लोगो की बनी मुसीबत षविकास की दावों की खुली पोल जल भराव से खुली पोल मन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने नगर आयुक्त श्री जैनेंद्र कुमार जी से मिलकर सभी वार्डो की समस्याओं को लेकर दिया मांग पत्र और कहा कि व्याप्त जलभराव, जाम नालियों और बदहाल सड़कों की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हल्की बारिश के बाद ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जा रही हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। इस समय लगातार नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है परंतु जहां गंदगी है वहां नहीं, केवल सड़को पर फोटो शूट हेतु दिखावे का काम जारी है।सरोज यादव ने कहा कि क्षेत्र की कई सड़कों पर जलभराव के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।नालियों की सफाई न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है।उन्होंने कहा कि नगर निगम स्वछता अभियान में फोटो खिंचवाने में व्यस्त है सरकार विकास के बड़े–बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यदि समय रहते नालियों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत कराई गई होती तो आज जनता को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। बरसात का मौसम आ गया है हमारी नगर आयुक्त से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण कराकर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जाम नालियों की सफाई, टूटी सड़कों की मरम्मत और नियमित फॉगिंग की व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के प्रति प्रशासन का उदासीन रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर जनहित में आंदोलन करने को बाध्य होगी। हमारे साथ महिला सभा महासचिव डॉ निशात अख्तर, कोषा अध्यक्ष पूनम यादव, उपाध्यक्ष राजकुमारी कोरी, यशोमती कोरी उपस्थिति रही।